मूल्य 1 रु.

वर्षः 10 - अंक : 233, मुंबई, बुधवार, 25 नवंबर, 2020 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त (R)

अब हर सच होगा उजागर

॥ शुभ लाभ ॥
MIX MITHAI

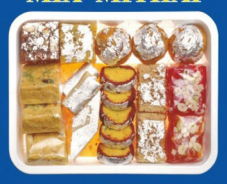

• मोतीचूर लड्डू • काजू कतरी • काजू रोल
• बदाम बर्फी • मलाई पेड़े • रसगुल्ले
MM MITHAIWALA
Malad (W) Tel. : 288 99 501

मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का टेस्ट सफल

400 किमी तक आवाज से तीन गुना रफ्तार से करेगी वार

नई दिल्ली। सेना ने देश में बनी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन का मंगलवार को कामयाब परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ब्रह्मोस का यह परीक्षण तयशुदा ट्रायल्स की सीरीज का हिस्सा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा- अंडमान-निकोबार में सुबह करीब 10 बजे ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया। टेस्ट पूरी तरह कामयाब रहा। आने वाले दिनों में एयरफोर्स और नेवी भी ब्रह्मोस के हवा और समुद्र से फायर किए जाने वाले वर्जन का परीक्षण करेंगी। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए जानी जाती है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी डिजिटल स्ट्राइक

43 ऐप्स बैन, इनमें जैक मा की कंपनी अलीबाबा के 4 ऐप और 10 करोड़ डाउनलोड वाला स्नैक वीडियो शामिल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 43 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया। केंद्र ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69ए के तहत ये बैन लगाया है। केंद्र ने बताया कि ये ऐप ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, जिनसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए खतरा हैं। (शेष पृष्ठ 3 पर)

अलीबाबा ग्रुप के कुछ प्रमुख ऐप, शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप स्नैक वीडियो, बिजनेस कार्ड रीडर ऐप कैम कार्ड, ट्रक और ड्राइवर एग्रीगेटर लालमूव आदि कुछ प्रमुख ऐप हैं जो इस बार ब्लॉक किए गए हैं

148 दिनों में 267 ऐप्स बैन किए गए: गलवान झड़प 15 जून को हुई थी। चीन को कड़ा संदेश देने और उस पर दबाव बनाने के लिए सरकार ने पहली बार चीनी ऐप्स बैन किए। इसके बाद 148 दिन के भीतर 267 ऐप्स पर बैन लगाया जा चुका है और इनमें ज्यादातर ऐप चाइनीज हैं।

समुद्री सीमा पर... पाक की हलचल

गुजरात से लगी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में जंगी जहाज और हेलिकॉप्टर दिखे

सुरक्षाबल सतर्क

संवाददाता

कच्छ। अरब सागर में गुजरात से लगी पाकिस्तान की समुद्री सीमा में अचानक पाकिस्तानी मरीन की हलचल बढ़ गई है। इसके बाद भारतीय एजेंसियां और सुरक्षाबल सतर्क हो गए हैं। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मरीन बाउंड्री-लाइन के पास पाक मरीन के 5 जंगी जहाजों और एक हेलिकॉप्टर नजर आया। बाउंड्री लाइन पर नजारा ऐसा था, मानो मरीन की एक्सरसाइज चल रही हो। (शेष पृष्ठ 3 पर)

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

थम गई तेजस

भारत की पहली निजी ट्रेन का संचालन रद्द करने का फैसला जितना चिंताजनक है, उतना ही विचारणीय भी। इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा संचालित इस ट्रेन के पहिए आज के बाद रुक जाएंगे। लखनऊ-दिल्ली और मुंबई-अहमदाबाद के बीच तेजस एक्सप्रेस के परिचालन को रोकने का निर्णय किया गया है। यह गौर करने वाली बात है कि कोरोना संक्रमण की शुरूआत में लॉकडाउन से पहले ही 19 मार्च को तेजस का संचालन बंद कर दिया गया था। त्योहारों को देखते हुए तेजस एक्सप्रेस का 17 अक्तूबर को परिचालन फिर शुरू किया गया था। अब परिचालन को यात्रियों की कमी की वजह से अगर रद्द करना पड़ रहा है, तो यह विमर्श का गंभीर विषय है। जहां इन्हीं मार्गों पर दूसरी सार्वजनिक ट्रेनों का संचालन आसानी से हो रहा है, वहीं तेजस को अगर यात्रियों की कमी का सामना करना पड़ा है, तो इसके कुछ संकेत बहुत स्पष्ट हैं। पहला संकेत, इन ट्रेनों का संचालन जिस लागत, कीमत और गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए, शायद वैसा नहीं हो पा रहा है। जब सार्वजनिक ट्रेनों की पटरी पर वापसी सामान्य नहीं हो पा रही है, जब ज्यादातर विशेष ट्रेनों के जरिए ही यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने को विवश हैं, तब इन निजी ट्रेनों के पास एक मौका था। वे अपनी सेवा से यात्रियों के दिल में जगह बना सकती थीं। कोरोना के समय सामान्य ट्रेनों में सफर सुरक्षित नहीं माना जाता है, तो क्या तेजस के जरिए यह कोशिश नहीं होनी चाहिए थी कि यात्रा को पूर्ण सुरक्षित बनाया जाता? बेशक, युग कोई भी हो, निजी क्षेत्र को अपनी सेवा गुणवत्ता के जरिए ही आगे बढ़ने में सहूलियत हो सकती है। यदि निजी सेवा को भी सरकारी सेवा की तरह ही चलाया जाएगा और उसकी लागत-कीमत ज्यादा वसूली जाएगी, तो निजी सेवा को जारी रखना आसान नहीं होगा। तेजस का बंद होना एक संकेत है, भारत में निजी क्षेत्र या निजी रेल सेवा वह जरूरी अंतर नहीं पैदा कर सकी, जो उसे अपनी जगह बनाने के लिए करना चाहिए था। कुछ महीने बाद भले तेजस को फिर शुरू कर दिया जाए, लेकिन जिस उम्मीद से तेजस की शुरूआत हुई थी, उसमें नाकामी ही हाथ लगी है। यह सवाल पहले ही उठाया जा रहा था कि महंगी तेजस रेल सेवा को यात्री कहां से मिलेंगे? तेजस के बंद होने से आईआरसीटीसी की छवि को भी नुकसान हुआ है। यह भी कहा जाएगा कि चूंकि आईआरसीटीसी सरकार से जुड़ी इकाई है, इसलिए तेजस पूरी तरह से निजी सेवा नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या तेजस को भी सरकारी ढर्रे पर चलाने की कोशिश हुई है और सेवा को आकर्षक बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयोग या नवाचार नहीं किए गए हैं? तेजस की नाकामी से एक और बात सामने आई है कि निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए ही सक्रिय रहता है और अर्थव्यवस्था व देश जब मुसीबत में हो, तब निजी क्षेत्र अपने हाथ खड़े करने में भलाई समझ लेता है। तेजस से सबक सीखते हुए सार्वजनिक रेल सेवा में ही ज्यादा से ज्यादा सुधार और सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। उन्हीं सेवाओं और उपक्रमों को पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ाना चाहिए, जो मुसीबत या जरूरत के समय काम आएं? सार्वजनिक सेवा में निजी क्षेत्र को अपनी जगह बनाने के लिए कुछ अलग ही आदर्श गढ़ने पड़ेंगे।

सबक सीखने का समय

दिल्ली के एक प्रख्यात महाविद्यालय की 19 वर्षीय छात्रा ऐश्वर्या रेड्डी के आत्महत्या प्रकरण ने कई प्रश्न पीछे छोड़ दिए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली ऐश्वर्या अपने परिवार के लिए यह संदेश छोड़ गई है, मेरी शिक्षा को आगे जारी रखना मेरे परिवार पर असहनीय बोझ बनता जा रहा है और मैं बिना पढ़े नहीं रह सकती। 12वीं कक्षा में ऐश्वर्या के 98.5 फीसद अंक थे। उसके पिता मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। उन्होंने दो लाख रुपये में अपना आधा मकान गिरवी रखकर बेटी को दिल्ली में प्रवेश दिलाया था। इस प्रतिभावान छात्रा को ह्यइंस्पायरह्ल योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन मिली नहीं थी। लिहाजा पिता लैपटॉप नहीं खरीद पाए थे। उनकी आमदनी पर भी कोरोना संकट का प्रभाव पड़ा था, मगर बेटी की पढ़ाई जारी रखने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। इधर महाविद्यालय ने अपने नियमों के अनुसार ऐश्वर्या से छात्रावास खाली करने को कह दिया।

कुल मिलाकर हर तरफ से संसाधनों की कमी का दबाव ऐश्वर्या पर इतना बढ़ गया, जिसमें उसके सारे सपने, आशाएं और कुछ कर दिखाने की इच्छाशक्ति तिरोहित हो गई। अब दिल्ली के महाविद्यालयों में चर्चा तथा प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं कि उन विद्यार्थियों का ध्यान रखा जाए, जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं हैं। दरअसल यह समस्या केवल दिल्ली के महाविद्यालयों या उच्च शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। सबसे अधिक समस्या तो स्कूलों (विशेष रूप से सरकारी स्कूलों) में उन बच्चों की है, जिनके घरों में स्मार्टफोन नहीं हैं। यदि हैं भी तो कई बच्चों वाले परिवार के लिए काफी नहीं हैं। अगस्त 2020 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी और अपर

प्राइमरी स्कूलों में 1.8 करोड़ बच्चों में से केवल 50 फीसद की पहुंच ही ऑनलाइन शिक्षा तक हो सकी है। प्रथम संस्था की वार्षिक असर रिपोर्ट 2018 में उत्तर प्रदेश में करीब 91.7 फीसद परिवारों के पास फोन थे, मगर मात्र 32.6 प्रतिशत के पास ही स्मार्टफोन थे। यही प्रतिशत 2019 में क्रमशः 94.7 और 48 हो गया। 2020 में कोरोना के कारण स्मार्टफोन या लैपटॉप की उपलब्धता में किसी बड़ी वृद्धि की अपेक्षा संभव नहीं है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अभी भी बंद हैं, सभी ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं। वंचित बच्चों में इससे मानसिक तनाव बढ़ रहा है। गैजेट की अनुपलब्धता प्राणघातक स्थिति तक न पहुंचे, इसके लिए सरकार, समाज और संस्था को एकसाथ मिलकर विचार-विमर्श कर समाधान ढूंढना चाहिए। जिस समाज में बड़ी संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हों, उसे सामूहिक रूप से सजग, सतर्क और संवेदनशील बनना ही पड़ेगा। हमारे समाज की मान्यता तो यही होनी चाहिए कि किसी भी जीवन को बचाने के लिए हरसंभव प्रयत्न किए जाएं। क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि भारत में हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करता है? जनवरी 1995 से लेकर 2019 के अंत तक देश में 1.7 लाख छात्रों ने आत्महत्या की। 2019 में 10,335 छात्रों ने आत्महत्या की। 2016 और 2017 में यह आंकड़ा 9,478 और 9,905 रहा। स्पष्ट है कि यह संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। आर्थिक कारणों से अनेक आत्महत्याएं होती हैं, जैसा कि ऐश्वर्या के साथ हुआ।

परिवार के उस कष्ट की भी कल्पना कीजिए, जब उनकी बेटी स्कूल/कॉलेज जाते समय असामाजिक तत्वों की छेड़छाड से तंग आकर आत्महत्या करती है। इनमें अनेक प्रकरण ऐसे भी होते हैं, जहां पुलिस के पास महीनों पहले से लिखित शिकायत होती है, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बोर्ड परीक्षा का भय और पाठ्यक्रम का बोझ भी इसका कारण है। एक बड़ा कारण परीक्षा में असफल होना या अपेक्षित अंक प्रतिशत प्राप्त न कर पाना भी है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के कई प्रसिद्ध तथा साख वाले कॉलेजों में स्नातक कक्षा में प्रवेश का कटऑफ कई विषयों में शत प्रतिशत तक जाता है। 99 फीसद अंक प्राप्त करने वाला छात्र और उसका परिवार हताशा में डूब जाते हैं। यह चर्चाएं भी सुनाई देती हैं कि इस स्थिति को भांपकर कई स्कूल विशेष प्रयास करते हैं कि उनके विद्यार्थी शत-प्रतिशत अंक ही पाएं! स्कूल बोर्ड भी अब संभवतः इसका ध्यान रखने लगे हैं। यह उचित है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इनका संज्ञान लिया है। अब पाठ्यक्रम का बोझ घटाया जाएगा, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करने की छूट होगी, परीक्षा सुधार की अनेक संभावनाओं को व्यावहारिक रूप से लागू किया जाएगा। आशा करनी चाहिए कि इससे स्थिति सुधरेगी।

हालांकि कई ऐसे कारण हैं जिन्हें समाज और पालकों के सक्रिय सहयोग के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा पूरी करने वाला हर बच्चा जानता है कि उच्च शिक्षा के लिए उसे घोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उसके अंक कितने ही अच्छे क्यों न आ रहे हों, अनिश्चितता उसके मस्तिष्क पर हावी रहती है। माता-पिता का यह हाल बच्चे से पहले ही प्रारंभ हो चुका होता है। इनमें से अनेक अपनी क्षमता अनुसार तीन-तीन, चार-चार ट्यूशन लगा चुके होते हैं। कक्षा 10 के बाद के दो वर्ष सबसे अधिक कठिन होते हैं। एक तरफ कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा का तनाव और दूसरी ओर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा की चुनौती। इसका सबसे सटीक उदाहरण है राजस्थान के शहर कोटा का कोचिंग केंद्र बनना। वैसे अब ऐसे कोचिंग केंद्र लगभग हर बड़े शहर में मिल जाएंगे। इन केंद्रों में आने वाले बच्चों में बड़ी संख्या उनकी होती है, जो अपनी रुचि के अनुसार नहीं, बल्कि माता-पिता की रुचि के विषय पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं। चूंकि ये शुद्ध रूप से धनार्जन के केंद्र होते हैं, अतः यहां बच्चों के मनोभावों को जान-समझकर पढ़ाने में किसी की रुचि नहीं होती है। कोंचिंग के लगभग अनिवार्य रूप में स्वीकृत हो जाने का कारण है सरकारी स्कूलों की लगातार घटती साख, उनमें नियमित अध्यापकों की कमी, लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक शिक्षा के उच्च स्तरीय संस्थानों की प्रवेश परीक्षा का समय के साथ बदल न पाना। ये सब ऐसे कारण हैं, जिन पर काबू पाना असंभव नहीं है, मगर उसके लिए आवश्यक इच्छाशक्ति और लगनशीलता की कमी सरकार, अध्यापक वर्ग और समाज में अपनी पैठ बना चुकी है।

एक नया भारत

कहां तो हम ध्वनि की गति से तीन गुनी रफ्तार (मैक-3) से हवा में उड़कर और चांद-सितारों पर टूरिज्म विकसित करने के मंसूबों के साथ प्रकृति पर पूर्ण विजय का एलान कर रहे थे और कहां कोरोना रूपी एक अदृश्य अर्ध-जीव (एक ऐसा खतरनाक प्रोटीन जो मानव शरीर में स्वयं अपना प्रसार कर लेता है) पूरी दुनिया में मानव अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया। हालांकि मानव में एक खास बात है कि वह संकट तो उत्पन्न करता है, परंतु उसका हल भी खुद ही ढूंढ निकालता है। कोरोना वैक्सीन अब एक सच्चाई बन रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि कोई दूसरा कोरोना फिर हमला नहीं करेगा, हमारे अस्तित्व

को चुनौती नहीं देगा और हम साल भर नई वैक्सीन की तलाश नहीं करते रहेंगे? इस महामारी में दुनिया भर में लाखों जानें गंवाने, 88 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से करीब आठ ट्रिलियन डॉलर (भारत की कुल जीडीपी का तीन गुना) का नुकसान उठाने और करोड़ों लोगों की नौकरियों की तबाही झेलने के बाद दुनिया को अब समझ में आया है कि विकास की हमारी परिभाषा गलत थी और प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल ही स्थायी विकास दे सकता है। दरअसल घटनाएं या दुर्घटनाएं कई बार किसी देश का भाग्य बदल देती हैं। इसका कारण होता है समाज की सामूहिक चेतना में गुणात्मक परिवर्तन। परमाणु विध्वंस से उभरा जापान इसका उदाहरण है। मार्टिन लूथर की तत्कालीन ईसाई धर्म-व्यवस्था पर सवाल उठाते 95 थीसिस ने 16वीं सदी में पश्चिमी जगत में पुनर्जागरण को नई दिशा दी।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

समाचार

मुंबई, बुधवार
25 नवंबर, 2020

03

ईडी का दुरुपयोग कर महाराष्ट्र सरकार गिराने का ख्वाब देखने वाले मूर्ख: राउत

मुंबई। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ईडी की रेड के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने सरनाईक का बचाव करते हुए कहा है कि अगर महाराष्ट्र में एजेंसी का दुरुउपयोग करके कोई यहां की सरकार को गिराना चाहता है तो वह मूर्ख है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों घटक दल एक साथ में हैं। उनका एक-एक विधायक पार्टी और सरकार के साथ है। केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में विधायकों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह रणनीति यहां पर काम नहीं आने वाली है। केंद्र सरकार दोबारा महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही

है। बीजेपी और केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर लें, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। राउत ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं लेकिन उन पर कोई भी जांच नहीं होती है। इससे पहले शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के ठाणे शहर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने रेड डाली। ईडी के अधिकारियों द्वारा प्रताप सरनाईक के परिजनों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (आर्थिक लेन-देन) की जांच की जा रही है। मुंबई और ठाणे समेत 10 जगहों पर रेड की बात सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक यह रेड टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और विधायक प्रताप सरनाईक के बीच हुए आर्थिक लेन-देन को लेकर हुई है।

किस मामले में हुई रेड?: प्रवर्तन निदेशालय ने यह छापेमारी किस मामले में की है। फिलहाल इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है लेकिन कुछ भी समय में इसके स्पष्ट होने के आसार हैं। प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि प्रताप सरनाईक और उनके परिवार ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को छिपाया है। इसके अलावा कोई भी घोटाला इसकी आड़ में किया गया है क्या? इसकी जांच ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। प्रताप सरनाईक खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। शिवसेना में उनको एक तेजतर्रार नेता के तौर पर जाना जाता है।

ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है शिवसेना: केंद्र की भाजपा सरकार पर शिवसेना अक्सर केंद्रीय जांच एजेंसी और खासतौर पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। फिलहाल शिवसेना ने भी इसे बदले की राजनीति और भाजपा के विरुद्ध बोलने वाले नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास बताया है। प्रताप सरनाईक या उनके परिवार ईडी की तरफ से किसी भी प्रकार का समन भी नहीं भेजने की बात सामने आ रही है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि ईडी बिना होम वर्क के नहीं जाएगी। अगर सरनाईक ने भ्रष्टाचार किया होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए।

फेरीवालों के लाइसेंस की खरीदी-बिक्री पर रोक से बीएमसी को नुकसान

मुंबई। अधिकृत फेरीवालों के लाइसेंस की खरीदी व बिक्री पर रोक से बीएमसी को हर साल लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। फेरीवाले अपने लाइसेंस एक-दूसरे को बेच व खरीद सकें, इसपर जल्द से जल्द एक नीति बनाई जाए। यह बात मेयर किशोरी पेडणेकर ने फेरीवालों के मुद्दे पर आयोजित बैठक में कही। मेयर पेडणेकर ने कहा कि फेरीवालों के लाइसेंस की पहले बिक्री व खरीदी की जाती थी, जिससे बीएमसी को राजस्व प्राप्त होता था। वर्ष 2012 से इसे बंद कर दिया गया है। इससे बीएमसी को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसलिए जल्द ही एक ऐसी नीति बनाई जाएगी,

जिससे फेरीवाले अपने लाइसेंस को बेच व खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या शुल्क लगाया जाए, यह निश्चित होना चाहिए। महापौर ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर हुई बैठक में अधिकारियों को फेरीवालों के लाइसेंस की खरीदी व बिक्री की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। मेयर ने कहा कि सूचना यहां तक मिली है कि फेरीवाले अपना लाइसेंस भाड़े पर भी दे रहे हैं। इससे बीएमसी के राजस्व पर असर पड़ रहा है। इसलिए अधिकृत फेरीवालों को लाइसेंस की खरीदी व बिक्री की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसके पास मुंबई में पंद्रह वर्ष रहने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वह इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसकी नीति निर्धारित करते समय स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बता दें कि मुंबई में फेरीवालों की समस्या का अभी तक बीएमसी हल नहीं निकाल पाई है। मुंबई में फेरीवाला जोन कहां हो, इस पर भी विवाद है।

टल सकता है महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालिन सत्र

मुंबई। 7 दिसंबर से शुरू होने वाला महाराष्ट्र विधानमंडल का शीलकालीन सत्र टल सकता है। चर्चा है कि शीतकालीन सत्र और आगामी बजट सत्र को एक साथ ही समाहित किया जाए। हालांकि, इस संबंध में 2 दिसंबर को विधानमंडल दोनों सदनों के कामकाज समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते संसद का शीतकालीन सत्र टालने की खबरें आ रही है। महाराष्ट्र विधानमंडल

इस पर विचार कर रहा है कि क्यों नहीं राज्य सरकार भी शीलकालीन सत्र की बैठक टाल दे। इससे पहले विधानमंडल कामकाज की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया था कि कोरोना के चलते शीतकालीन सत्र नागपुर की बजाय मुंबई में रखा जाए। उस समय बैठक में तारीख को लेकर निर्णय लिया गया था। तय हुआ था कि 2 दिसंबर को कामकाज समिति की बैठक निर्णय लेंगे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का टेस्ट सफल

ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है। लेकिन, इसकी स्पीड 2.8 मैक ही रखी गई है। यह आवाज की रफ्तार से तीन गुना तेज है। पिछले ढाई महीने में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्र-1 समेत कई मिसाइलों के टेस्ट किए हैं। रुद्र-1 को 2022 में सेना में शामिल करने की तैयारी है। भारत ने एलएसी के अलावा, चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कई इलाकों में ब्रह्मोस की तैनाती की है। वायुसेना ने पिछले दिनों ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से फायर किए जाने वाले वर्जन का टेस्ट किया था। बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट से किया गया यह टेस्ट भी कामयाब रहा था। वायुसेना 40 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल फिट करने की तैयारी कर रही है। इससे हर मौसम में जमीन या समुद्र में किसी भी टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। नेवी ने भी पिछले महीने जंगी जहाज आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। गहरे समुद्र में इसके जरिए 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है।

चौथी डिजिटल स्ट्राइक

बैन की गईं 43 ऐप्स में से 14 डेटिंग, 8 गेमिंग ऐप्स, 6 बिजनेस और फाइनेंस और एक इंटरटेनमेंट ऐप शामिल हैं। चीनी ऐप टिकटॉक को बैन कर चुकी केंद्र सरकार ने अब पॉपुलर चैट ऐप स्नैक वीडियो को बैन किया है। ये सिंगापुर बेस्ड चाइनीज सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। टिकटॉक बैन होने के बाद यूजर्स के लिए ये सबसे बड़ा ऑप्शन बनी और महज 2 महीनों के अंदर करीब 5 करोड़ यूजर्स बढ़ गए। सबसे ज्यादा यूजर्स भारत में हैं। इसके अलावा चीन के बिजनेस टायकून जैक की कंपनी अलीबाबा की भी 4 ऐप्स पर बैन लगाया गया है।

केंद्र ने 4 बार ऐप्स के खिलाफ एक्शन लियाः 29 जून को 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। गलवान झड़प के बाद ये फैसला लिया गया। 27 जुलाई को 47 ऐप बैन किए गए थे। सरकार ने यह कदम तब उठाया था, जब लद्दाख में तनाव बढ़ रहा था और चीनी सैनिकों ने दो बार घुसपैठ की कोशिश की थी। 2 सितंबर को सरकार ने पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन किया था। पबजी को 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। 24 नवंबर को 43 मोबाइल ऐप्स बैन किए गए। फैसला इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर की गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने 18 सितंबर को वीचैट और टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स को बैन किया था। 20 सितंबर से यह बैन लागू होना था और 12 नवंबर को पूरी तरह से ऐप्स को बंद किया जाना था, लेकिन मामला अदालतों में उलझा रहा। ट्रम्प प्रशासन अक्टूबर में भी प्रयास कर रहा था कि बैन लागू रहे। हालांकि, अब चुनाव के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस वजह से यह बैन फिलहाल प्रभावी नहीं है।

समुद्री सीमा पर पाक की हलचल

हालांकि, पाकिस्तान की यह एक्टिविटी उसकी ही समुद्री सीमा में हो रही थी, लेकिन भारतीय सुरक्षाबलों की पैनी नजर थी। कुछ घंटों की एक्टिविटी के बाद सभी जहाज और हेलिकॉप्टर कराची की तरफ रवाना हो गए। पाक मरीन, भारतीय मछुआरों को परेशान करते रहते हैं। आए दिन मछुआरों के अपहरण और उन पर फायरिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। सितंबर में पाक मरीन ने आठ नावों में सवार 40 भारतीय मछुआरों का अपहरण कर लिया था। फिलहाल ये सभी कराची की जेल में हैं, जिन्हें छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब कच्छ (गुजरात) बॉर्डर तक आ पहुंचा है। कच्छ से लगे सरहदी इलाके में चीनी कंपनियों को जमीन भी दे दी गई है। ये कंपनियां यहां सड़क कंस्ट्रक्शन के अलावा खनन और पावर प्लांट लगाने का काम कर रही हैं। चीन से शुरू होने वाला चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कच्छ से लगे पाकिस्तान बार्डर पर ही खत्म होता है।

समंदर के खारे पानी को मीठा बनाएगी महाराष्ट्र सरकार

पानी की किल्लत से मुक्त होगी मुंबई

मुंबई। मुंबई में गर्मी के मौसम में खासतौर पर मई और जून के महीने में मुंबई के नागरिकों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। हर साल होने वाली इस दिक्कत को हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने का फैसला किया है। इस परियोजना के तहत 200 एमएलडी पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को हुई एक बैठक में यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अक्सर मॉनसून देरी से आता है जिसकी वजह से मई और जून के महीने में 10 से 15 फीसदी की पानी कटौती करनी पड़ती है। इस दिक्कत को रोकने के लिए समुद्र के खारे पानी को मीठा करके मुंबई के नागरिकों कि इस समस्या को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के कई देशों में ऐसी परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। जबकि कुछ देशों में इन पर काम शुरू है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्लांट को मनोर इलाके में स्थापित किया जाएगा। मनोर इलाके में पानी की गुणवत्ता काफी अच्छी है और जरूरी मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। उन्होंने कहा की इस परियोजना को अगर सौर ऊर्जा के जरिए चलाया जाए तो लागत और भी कम हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोर में सरकारी जमीन और सड़कें उपलब्ध हैं। साथ ही इस जगह पर कोई शहरी कॉलोनी भी नहीं है। इसलिए यह परियोजना बिना किसी रूकावट के पूरी हो सकती है।

पूरा होने में तीन साल लगेंगे: इस परियोजना को पूरा होने में तकरीबन ढाई से 3 साल का वक्त लग सकता है। इसे बनाने के लिए तकरीबन 25 से 30 एकड़ की भूमि का उपयोग किया जाएगा। जहां 200 एमएलडी पानी वाली इस परियोजना को स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में तकरीबन 16 सौ करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। समुद्र के खारे पानी को मीठा करने के लिए 3 से 4 पैसे प्रति लीटर खर्च होने का अनुमान है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश,

8 जनवरी को बहन के साथ कंगना को मुंबई पुलिस के सामने होना पड़ेगा पेश

मुंबई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस के सामने 8 जनवरी को पेश होना पड़ेगा। मुंबई पुलिस की तरफ से तीन बार समन पर पेश नहीं होने के बाद कंगना रनौत और उनकी बहन की तरफ केस को रद करने का अनुरोध किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने नहीं माना। जज ने कंगना रनौत और उनकी बहन की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि वे एक पारिवारिक शादी में व्यस्त थीं। कंगना के वकील ने जिरह करते हुए कहा- हमारे मुवक्किल नहीं पेश हो पाई क्योंकि एक शादी हो रही थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ बयान भिजवाया था। जिसके बाद जज ने जवाब दिया कि जो भी चीजें थी, आपको समन का आदर करना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर क्यों कंगना रनौत पर देशद्रोह का केस लगाया गया। देशद्रोह चार्ज का हवाला देते हुए जस्टिस शिंदे ने कहा- 'क्या आप देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? 124ए?' इसके बाद मुंबई पुलिस के वकील ने सवाल करते हुए कहा, अगर वे गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहते हैं तो वे जल्द से जल्द आएं। उनके लिए ऐसा क्या खास है कि उन्हें जनवरी तक का इंतजार करना चाहिए। गौरतलब है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर रिपोर्ट में कंगना और उनकी बहन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और साम्प्रदायिक तनाव को भड़काने का आरोप लगाया गया है। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली कल और आज मिलाकर तीन बार मुंबई पुलिस के समन पर नहीं पहुंची हैं।

मून व्हाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट- MWFIFF 2020 हुआ डिजिटल

जैकी श्रॉफ को मिला मून व्हाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड

यहां बताया गया है कि तीसरे एडिशन से क्या उम्मीदें जगीं

नए नॉर्मल में काम करना सीखना आज बहुत महत्वपूर्ण है और मनोरंजन इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है! भारत में शॉर्ट फिल्मों का आखिरकार दौर आ गया है। आज, कुछ सबसे बेहतरीन निर्देशक और ऐक्टर्स कम बजट के साथ कम लंबाई की फि ल्में रिलीज करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं और पहले से कहीं अधिक प्रभाव डाल रहे हैं। तीसरे मूनव्हाइट फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट-एम डब्ल्यू एफ आई एफ एफ (MWFIFF) 2020 ने इस वर्ष डिजिटल रूप धारण कर लिया है और सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए इस वर्ष की कुछ प्रतिष्ठित फिल्मों की स्क्रीनिंग और पुरस्कार समारोह डिजिटल रूप से किया गया। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने फिल्म पाठ-द लेसन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता जबकि ऋतुराज के. सिंह और पल्लवी जोशी ने फिल्म 'पेनफुल प्राइड' में अपने अभिनय के लिए पुरस्कार जीता। इसके अलावा, अमेरिका की कई फिल्मों ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। उनमें से एक फिल्म है 'किस द ग्राउंड' जिसे जॉश टिकेल, रेबेका टिकेल मे डायरेक्ट किया है और इसमें हॉलीवुड अभिनेता वुडी हैरेल्सन ने अभिनय किया है, उन्हें भी इस फिल्म महोत्सव में अवॉर्ड से नवाजा गया। इस फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक और निदेशक देवाशीष सरगम राज ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री ने कठिन समय देखा है लेकिन हम सभी को अपना काम जारी रखने और अपना अच्छा काम करने की आवश्यकता है। इस वर्ष अमेरिका और भारत की कुछ दिलचस्प शॉर्ट फिल्में देखी गईं। यह दिलचस्प है कि शॉर्ट फिल्में कई युवा और प्रतिभाशाली और साथ ही सीनियर अभिनेताओं के लिए रास्ते खोल रही हैं, जो दिलचस्प विषय के साथ इंसाफ कर सकते हैं।

फिर वही परेशानी: गुजरात में दोबारा लॉकडाउन लगने के डर से पलायन शुरू, परिवार समेत श्रमिक अपने घर हो रहे रवाना

संवाददाता

सूरत। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फिलहाल चार बड़े शहरों (अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट) में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात अब लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके डर से एक बार फिर मजूदरों का पलायन शुरू हो गया है। सूरत के इंडस्ट्रियल शहर वापी, वलसाड से हजारों की तादाद में मजदूर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए नेशनल हाईवे पर जमा हो रहे हैं। मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद सूरत जिले के करीब 70 फीसदी वर्कर्स अपने घर लौट गए थे। अनलॉक के बाद इनमें से करीब 60 फीसदी मजदूर वापस काम के लिए लौट आए थे और जीवन की गाड़ी को फिर से व्यवस्थित करने में जुट गए थे। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से पुराने हालात पैदा कर दिए हैं। सूरत जिले में ज्यादातर मजदूर मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और बिहार के हैं, जिनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है।

प्राइवेट वाहनों और ट्रकों से हो रहे रवाना

ट्रेनों में टिकट न मिलने और लोकल ट्रेनों के न चलने के चलते वर्कर्स नेशनल हाईवे पर इकट्ठे हो रहे हैं और यहां से बसों, प्राइवेट वाहनों और ट्रकों से रवाना हो रहे हैं। ज्यादातर वर्कर्स टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। इसलिए इनके पलायन से एक बार फिर इंडस्ट्रीज को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

पुलिस पर हमला मामला: अरनब की अग्रिम जमानत अर्जी पर 1 दिसंबर को सुनवाई

मुंबई। मुंबई पुलिस की एक महिला अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत संबंधी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। इस मामले में एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस ने दंपति और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के एक मामले में जब पुलिस 4 नवंबर को अरनब को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची, तो उन्होंने महिला अधिकारी पर कथित तौर पर हमला किया और सरकारी कर्मी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका। अरनब के वकील श्याम कल्याणकर ने कहा कि वे इस मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, अरनब को हिरासत में लेने का अनुरोध करने वाली अलीबाग पुलिस की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पांच दिसंबर तक के लिए टल गया, क्योंकि अलीबाग सत्र अदालत से संबद्ध न्यायाधीश याचिका पर

सुनवाई के लिए सोमवार को उपलब्ध नहीं हो सके। अरनब और अन्य आरोपियों को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने का मामला 2018 का है। इन पर आरोप है कि उनकी कंपनियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। इस मामले में 47 वर्षीय टीवी पत्रकार को गिरफ्तार करने के बाद अलीबाग में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के बजाय न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। इसके बाद अलीबाग पुलिस ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी की जमानत 11 नवंबर को स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद तलोजा जेल से रिहा किया गया था। फिलहाल अरनब और उनकी पत्नी सम्यव्रत राय गोस्वामी ने भी अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। अरनब और उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) और 506 (आपराधिक रूप से डराना/धमकी देना) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बुलढाणा हलचल

हर वार्ड में 200 से 300 फर्जी मतदाताओं की घुसपैठ की साजिश!

कांग्रेस-एनसीपी ने तहसीलदार को आंदोलन की चेतावनी दी

संवाददाता/अशफाक युसुफ

बुलडाणा। अगले वर्ष होने वाले नगरपालिका चुनावों के लिए, बुलडाणा में कुछ राजनेताओं और पार्टी नेताओं ने बुलडाणा शहर की मतदाता सूची में गांवों और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के नाम शामिल करने का फैसला किया है.कार्यक्रम गुप्त रूप से आगामी नगरपालिका परिषद चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में 200 से 300 नामों को शामिल करने के लिए बनाया गया है। ओ कांग्रेस और एनसीपी के पदाधिकारियों ने उनकी भागीदारी के बारे में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस संबंध में एक निवेदन तहसीलदार खंडारे को भी दिया गया है। सरकार द्वारा दिए गए नियमों के अनुसार, केवल 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों के नाम क्षेत्र में शामिल किए जाने चाहिए। जिसके लिए फॉर्म-6 भरना अनिवार्य है और फॉर्म -8 में, स्थानांतरण के बारे में नियम तैयार किए गए हैं। लेकिन आने वाली नगर परिषद चुनाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा फार्म 8 भी भरा जा रहा है। यह आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए एक चुनाव के लिए गलत है और यह अन्यायपूर्ण है और राजनीतिक लाभ के लिए यह गैरकानूनी काम किया जा रहा है। हर नगरपालिका परिषद के चुनाव में इसलिए, इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, मतदाताओं पर स्टाफ/बीएलओ। उनके खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने चाहिए।क्या यह व्यक्ति शहर और उस सूची क्षेत्र में रह रहा है? मजबूत साक्ष्य होना अनिवार्य होना चाहिए। निवेदन देने वालों मे शहर काँग्रेस अध्यक्ष दत्ता काकस, राष्ट्रवादी शहर काँग्रेस अध्यक्ष अनिल बावस्कर साथ ही ॲड. राज शेख और मंगेश बिडवे इन का समावेश है।

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यूपीएससी की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता

संवाददाता/अशफाक युसुफ

बुलडाणा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए इस वर्ष एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की है जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना के तहत, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को 12,000 रुपये का मासिक वजीफा और 14,000 रुपये की पुस्तक खरीद दी जाएगी। इस योजना के तहत, अनुसूचित जनजाति के कुल 50 उम्मीदवारों को 25 उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने यूपीएससी की पूर्व परीक्षा दी है और मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 25 उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। इस योजना को वर्ष २०२० से लागू किया जाएगा और छात्रों का चयन जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा और यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में वितरित की जाएगी।

राजस्थान हलचल

शादी समारोह पर निगरानी के लिए क्षेत्रवार अधिकारियों को किया नियुक्त

संवाददाता/सैय्यद अल्ताफ हुसैन

बीकानेर। कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने शादी समारोह पर निगरानी हेतु वैवाहिक भवनों के निरीक्षण के लिए 9 अधिकारियों की क्षेत्रवार नियुक्ति की है। ये अधिकारी जिले के नगरीय क्षेत्र में आयोजित होने वाले शादी समारोह में आमंत्रित अतिथियों की संख्या पर नियंत्रण के लिए निगरानी करेंगे आदेशानुसार अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग दीपक बंसल, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग डी.पी. सोनी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र मंजू नैण गोदारा, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल.डी.पंवार, अधीक्षण अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अशोक गोयल, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको जी.के शर्मा, उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां नवरंगलाल, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ओ.पी. किलानिया, उपनिदेशक कृषि जगदीश पूनिया क्षेत्रवार वैवाहिक भवनों में कोविड-19 गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। मेहता ने बताया अधिकारीयह सुनिश्चित करेंगे कि विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल न हो। 100 से अधिक लोगों के एकत्र पाए जाने पर 25000 रुपए का जुर्माना तथा यदि आयोजन की सूचना उप खण्ड मजिस्ट्रेट नही दी गई, सामाजिक दूरी नही रखने, फेस मास्क नही पहनने, सैनेटाइजर की उपलब्धता नही होने पर संबंधित से 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले- 'जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं'

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्कूल खोलने को लेकर भी लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। इस बीच एक निजी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं। सिसोदिया ने कहा है कि इस वक्त स्कूल शुरू करना बच्चों को कोरोना की तरफ ले जाने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमें सहयोग मिला है और हमने सहयोग किया भी है। इस समय आपस में लड़ने से हम कोरोना से नहीं लड़ सकते। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अभी स्कूल खुलने लायक परिस्थितियां नहीं है। अभी स्कूल खोलने का मतलब है कि अपने बहुत सारे बच्चों को कोरोना की तरफ ले जाना, वो ना आप चाहेंगे और ना मैं चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से हमें एक टीम के रुप में लड़ना चाहिए। हमने केंद्र से सहयोग मांगा है कि एक हजार आईसीयू बेड और मिल जाएं। प्रदूषण के मुद्दे पर सिसोदिया ने कहा कि पराली की वजह से भी कोरोना के मामलों में उछाल आया है।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

अर्थराइटिस को बढ़ाते हैं ये 5 फूड्स, गलती से भी ना करें सेवन

अक्सर, 40 से 50 साल की उम्र में होता है आर्थराइटिस ज्यादातर महिलाएं होती हैं शिकार तला हुआ, शरार, तंबाकू छोड़कर आर्थराइटिस के दर्द में आराम पाया जा सकता है।

आर्थराइटिस...कहने को तो यह 40 साल के बाद होता है, लेकिन आज की जीवनशैली के चलते, इसकी चपेट में 35 से ऊपर के लोग भी हैं। यह ज्यादातर महिलाओं को होता है, लेकिन पुरुष भी इसके शिकार होते हैं। इसमें जोड़ों का दर्द होता है और उस अंग पर सूजन भी आ जाती है। हालांकि, इसके ट्रीटमेंट के लिए पेन-किलर्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि अगर डाइट में वो चीजें खाई ही न जाएं, जिनसे सूजन और जोड़ों का दर्द हो, तो इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। वैसे तो आर्थराइटिस 100 तरह का है, लेकिन सबसे ज्यादा होते हैं- ऑस्टियो आर्थराइटिस और रुमेटॉयड आर्थराइटिस। जहां ऑस्टियो आर्थराइटिस का वार अक्सर उंगलियों, घुटनों और हिप्स पर होता है, वहीं रुमेटॉयड आर्थराइटिस हाथों और पैरों को दर्द से जकड़ लेता है। ऐसे में इन अंगों को दर्द के कारण हिलाने में भी दिक्कत होती है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हो तो, इसका रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसका कोई पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन इसे प्रॉपर मेडिकेशन और डाइट की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है।

आर्थराइटिस के संकेतः

जोड़ों में दर्द
लाली
सूजन
अंगों का काम न करना
अकड़न
ट्रीटमेंटः
आराम करना
ठंडी या गर्म सिकाई
वजन कम करना

एक्सरसाइज

जॉएंट रिप्लेसमेंट

इसके अलावा, ये हैं 5 फूड्स जिन्हें आर्थराइटिस के रोगियों को खाने से बचना चाहिए।

तला हुआ या पैकेज्ड फूड

रिसर्च के मुताबिक अगर डाइट में तला हुआ और पैकेज्ड खाना जैसे- फ्राइड मीट, फ्रोजन वेजिटेबल्स नहीं ले जाएं और इनकी जगह फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए जाएं, तो सूजन और दर्द को कम किया जा सकता है।

ओवर-हीटिड फूड

साल 2009 में हुई एक स्टडी में सामने आया की आर्थराइटिस के रोगियों को ओवर-हीटिड और ग्रिल्ड खाना खाने से भी बचना चाहिए। यानी खाने को ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं बनाना चाहिए।

शुगर

जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, फिर चाहे वो पानी हो, नमक या चीनी। ज्यादा मीठा खाने से भी सूजन बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट से केक, सोडा, चॉकलेट, मैदा आदि आउट कर दें।

डेयरी प्रोडक्ट्स

कहने को तो दूध, दही शरीर के लिए लाभदायक हैं। इनसे कैल्शियम मिलता है। लेकिन आर्थराइटिस के शिकार लोगों की हेल्थ के लिए ये बिलकुल भी हेल्दी नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि इन डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई ऐसा प्रोटीन होता है जो जोड़ों का दर्द तेज करता है। ऐसे में शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह पालक, टोफू, बीन्स और दाल ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए।

अल्कोहल और टबैको

शराब और तंबाकू शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनसे जोड़ों का दर्द तो तेज होता ही है, साथ ही शरीर को कई खतरनाक बीमारियां भी लग सकती हैं। हेल्दी जाएंट्स के लिए जरूरी है बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट।

ये 10 घरेलू नुस्खे सेहत के लिए हैं हानिकारक, कभी न करें इस्तेमाल

हर चीज का इलाज घर पर करना कई बार स्थिति को और अधिक खराब कर सकता है। इस स्लाइड शो में कुछ ऐसे घरेलू उपचार दिये गए है जो चीजों को ठीक करने की बजाय आपको संकट में डाल सकते हैं।

घरेलू नुस्खे के नुकसान

बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम घरेलू उपायों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्हें घर पर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ घरेलू उपाय जैसे मधुमक्खी के डंक पर ठंडा पानी डालने को परेशानी के तुरंत इलाज का प्रभावी तरीका माना जाता है। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए हर चीज का इलाज घर पर करना कई बार स्थिति को और अधिक खराब कर सकता है। इस स्लाइड शो में कुछ ऐसे घरेलू उपचार दिये गए है जो चीजों को ठीक करने की बजाय आपको संकट में डाल सकते हैं। ईयर कंडलिंग कई लोग कान के वैक्स से छुटकारा पाने के लिए खतरनाक घरेलू उपचार इयर कांडलिंग का इस्तेमाल करते हैं जो खुजली और जलन पैदा कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान जब मोमबत्ती के आकार के बीवैक्स कोन को कान के अंदर रखा जाता है और इसकी बाती को जलाया जाता हैं। तब बाती से निकलने वाली कुछ बूंदे कान के अंदर चली जाती है। इस तरह से इस प्रक्रिया के दुष्प्रभाव खतरनाक होते है। इस घरेलू उपाय से आप अपनी सुनने की क्षमता को भी खो सकते हैं। छोटे बच्चों के मसूडों पर शराब का इस्तेमाल छोटे बच्चे दांत निकालते समय बहुत अधिक दर्द महसूस करते है जिससे वह अधिक चिड़चिडे हो जाते हैं और इस कारण से वह काफी रोते भी हैं। बच्चों के दर्द को कम करने के लिए माता-पिता अपने बच्चों के मसूड़ों पर शराब को रगड़ना एक घरेलू उपाय मानते हैं। लेकिन इस घरेलू उपाय से काफी हद तक बचा जाना चाहिए क्योंकि शराब का बहुत प्रभाव बच्चों पर भी वैसे ही पड़ता है जैसे बड़ों पर। इसके अलावा यह जलन भी पैदा कर सकता है।

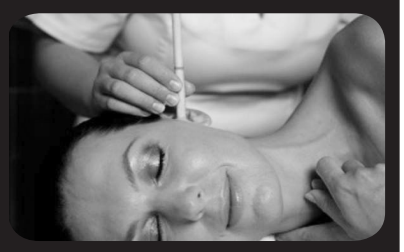

केमिकल्स वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स

इसके अलावा सुंदर दिखने के चलते कई लोग कोई भी क्रीम या कैमिकल प्रॉडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनसे भी चेहरे पर मुहांसे होते हैं। मुंहासों का ये कारण किशोरो में ज्यादा देखा जाता है। मुंहासों के इन कारणों के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। लेकिन आज हम आपको मुंहासे होने का एक ऐसा कारण बता रहे हैं जिसे पढ़कर आप निश्चत ही चौंक जाएंगे।

मुंहासे और तनाव

कई लोग चेहरे पर हद से ज्यादा मुंहासे होने या अन्य किसी तरह की खराबी के चलते डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा शोध बताते हैं कि जिस समय व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तब शरीर में कोर्टिसोल हार्मोंस का स्राव बढ़ जाता है जिसके कारण शरीर की त्वचा की ग्रंथियों से सीवम नामक हारमोन का स्राव ज्यादा होने लगता है जिसके कारण मुंहासे होते हैं। यानि कि मुंहासे और तनाव का गहरा संबंध है।

आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है आपके चेहरे पर पिंपल्स का कारण

आधुनिक लाइफस्टाइल और खानपान हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। आज हम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। तरह-तरह की मशीनों और उपकरणों से हमारे रोजमर्रा के काम और कई जटिल काम बेहद आसान हो गए हैं लेकिन कई बार इन उपकरणों का हमारे शरीर और दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। चेहरे पर पिम्पल या फिर अन्य तरह का कोई दाग चेहरे की खूबसूरती को बिल्कुल खराब कर देता है। खासतौर से आजकल यानि कि बदलते मौसम में चेहरे पर मुंहासे होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसके चलते चेहरे की सारी रंगत उड़ जाती है।

मोबाइल फोन और मुंहासे

आज के लोगों में खासकर युवाओं में स्मार्टफोन का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में ना सिर्फ जानते हैं बल्कि बखूबी इस्तेमाल करना भी जानते हैं। हालांकि इस चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। ज्यादा स्मार्टफोन का नकारात्मक प्रभाव हमारे दिमाग पर तो पड़ ही रहा है साथ ही हमारी स्किन पर भी पड़ रहा है

एक स्टडी के मुताबिक स्मार्ट फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में मुहांसों की समस्या बहुत बढ़ रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम काफी देर तक स्मार्टफोन को कान में लगाकर बात करते हैं तो उसमें चिपके कई तरह के बैक्टीरिया हमारी स्किन के पोर्स में चले जाते हैं, जिससे मुंहासे हो सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन ज्यातादर लोगों के हाथ में ही रहता है। जिसके चलते कई तरह के अनदेखे कीटाणु फोन में चिपक जाते हैं और जब वही हाथ हम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो कुछ ही देर में मुंहासे निकल आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं। स्मार्टफोन से बात करते वक्त हमेशा या तो ईयर फोन का इस्तेमाल करें और या फोन के इस्तेमाल के साथ चेहरे पर हाथ लगाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें।

तैलीय त्वचा को ज्यादा खतरा

मुंहासे ज्यादातर तैलीय त्वचा में होते हैं। मुंहासे होने के बड़े कारणों में दूषित खानपान और शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन हैं। मौसम में हुए बदलाव के कारण भी कई बार मुंहासे होने की समस्या हो जाती है। सर्दियों में तो मुंहासों के साथ बड़ी असमंजस वाली स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि ऐसे में त्वचा को नमी की भी जरूरत होती है और वह त्वचा को नहीं मिल पाती है। मुहांसे होने के और भी कई कारण होते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों पर कई तरह के दबाव हैं। ना सिर्फ बड़ों पर बल्कि छोटे-छोटे बच्चे भी आजकल पढ़ाई और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते तनाव के शिकार हो रहे हैं। तनाव भी चेहरे पर मुंहासे पैदा करने का एक

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

इस वजह से सलमान खान नहीं मनाएंगे अपने जन्मदिन का जश्न!

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान के ड्राइवर और स्टाफ मेंबर को बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद सलमान ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। हालांकि सलमान खान का कोरोना वायरस टेस्ट निगेटिव रहा। अब खबरें आ रही है कि सलमान खान ने अपने पनवेल फार्महाउस में होने वाले जन्मदिन के जश्न को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सलमान निगेटिव होने के बावजूद भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। स्टाफ मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाते ही सलमान खान ने तुरंत परिवार के सभी लोगों को टेस्ट के लिए बुलाया। सभी का परीक्षण नकारात्मक रहा। साथ ही खान परिवार के सभी समारोह रद्द हो गए हैं और इसमें उनका जन्मदिन भी शामिल है। हर साल सलमान अपने परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों के साथ पनवेल फार्म हाउस में अपना जन्मदिन मनाते हैं और नए साल का जश्न मनाने के बाद ही मुंबई लौटते हैं। लेकिन, इस बार ये सेलिब्रेशन रद्द हो गया। यहां तक कि सलमान के माता-पिता की शादी की सालगिरह 20 नवंबर को सिर्फ एक प्राइवेट सेलिब्रेशन तक सीमित रहेगी। बता दें कि 27 दिसंबर को सलमान अपना जन्मदिन मनाएंगे।

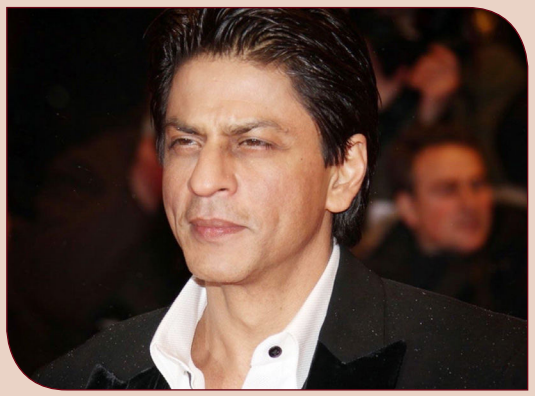

शाहरुख की फिल्म 'पठान' में एजेंट बनेंगी दीपिका

शाहरुख खान की कमबैक फिल्म 'पठान' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म में शाहरुख के अपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। और अब फिल्म से दीपिका पादुकोण के किरदार का खुलासा हुआ है। सुनने में आया है कि दीपिका इस फिल्म में एजेंट का किरदार निभाएंगी जिसे प्यार करना भी आता है और हड्डियां तोड़ना भी। खबरों की मानें तो बीते सोमवार से दीपिका पादुकोण ने भी फिल्म 'पठान' की शूटिंग शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'पठान' में दीपिका एक एजेंट का रोल निभाएंगी, जो शाहरुख के साथ उनके मिशन का हिस्सा होंगी। सूत्र के मुताबिक, यह फिल्म एजेंट्स की एक दिलचस्प दुनिया है और इसमें दीपिका जमकर स्टंट्स करेंगी। फिल्म का टाइटल भले ही शाहरुख पर आधारित है लेकिन दीपिका का किरदार भी काफी महत्वपूर्ण होगा। दीपिका का किरदार फिल्म 'पठान' में कुछ वैसा ही होगा जैसा 'टाइगर' फ्रेंचाइजी में कैटरीना कैफ का है। दीपिका इस फिल्म की शूटिंग किस्तों में करने वाली हैं क्योंकि इन दिनों वह शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग भी कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, वह दिसंबर के मध्य में शाहरुख के साथ अपने कुछ हिस्सों की शूटिंग करेंगी। इसके बाद एक्शन सीन्स की शूटिंग वह अगले साल जनवरी से जून के बीच करेंगी।

किंग खान के साथ अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बोली जूही

जूही चावला और शाहरुख खान की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों ने 'डर', 'राजू बन गया जेंटलमैन' जैसी कई फिल्में साथ की हैं और लगभग सारी फिल्में हिट भी रही हैं। आगे चलकर दोनों ने ड्रीम्ज अनलिमिटेड नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और उसके बाद पार्टनरशिप में एक आईपीएल टीम भी खरीदी। हाल ही में एक्ट्रेस ने किंग खान के साथ अपनी दोस्ती के बारे में खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि वह यंग जूही को क्या सलाह देंगी, तो उन्होंने कहा, मैं कहूंगी कि अपना अहंकार कम करो। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ऊंचे मुकाम पर थी और मेरी फिल्में अच्छी चल रही थी तो मैंने बहुत सारे मूर्खतापूर्ण फैसले किए। मुझे लगा कि सब मेरे बारे में है। मैंने उस समय कुछ मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए। उसके बाद मैं कहूँगी कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आओ और यह मैंने असल में शाहरुख से सुना है। एक समय था, जब मैं डर की शूटिंग कर रही थी और मेरी अपनी मां के साथ छोटा-सा झगड़ा हो गया और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि लोग मेरे आस-पास हैं और बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। एक्ट्रेस कहती हैं कि शाहरुख की सलाह हमेशा उनके साथ रही।